धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की घोषित नीति है- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में पर्यटन के प्रीसमिट सम्मेलन को संबोधित किया

जयपुर, 27 नवम्बर। गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विकास हो रहा है। इस वर्ष अगस्त माह तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक और 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं।**

प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है। भव्य किले, महल, हवेलियां, थार का मरुस्थल, वन्यजीव अभयारण्य, आस्था धाम और झीलों की उपलब्धता राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निराला प्रदेश बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस वर्ष अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात् करते हुए, राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 योजना के अंतर्गत, खाटूश्याम जी, करणी माता मंदिर, मालासेरी डूंगरी समेत, अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया है।

प्री-समिट में उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन अपर सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, हिन्दुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा सहित, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्यमी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद थे।

'स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों की जवाब देही तय की जाए'

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया तथा ओटीटी संस्थाओं द्वारा अपनाये गये मौजूदा स्व-नियमन ढांचे पर असंतोष व्यक्त किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री की निगरानी के लिए एक ''तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त'' नियामक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ गुरूवार को पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में ऑनलाइन शो ''इंडियाज गॉट लैटेंट'' से संबंधित कथित अश्लील सामग्री को लेकर दर्ज प्राथमिकी को एक साथ करने की मांग की गयी है। । इससे पहले न्यायालय ने ऑनलाइन अश्लीलता पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मामले के दायरे को बढ़ाया था। मुख्य न्यायाधीश ने स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी भी नियामक ढांचे की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, ''तो मैं अपना चैनल बनाता हूं, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं... किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए!'' उन्होंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ''विकृति'' को सही ठहराने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हार्डकोर सदस्य प्रदीप गुर्जर गिरफ्तार

एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स ने नाटकीय तरीके से गुरुग्राम की पॉश सोसायटी में उसे पकड़ा

जयपुर, 27 नवम्बर। एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स राजस्थान (एजीटीएफ) की टीम ने कार्रवाई करते हुए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक सक्रिय सदस्य और हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रदीप रावतों की ढाणी, वार्ड नंबर 15, कोटपूतली, का रहने वाला है। उसे गुड़गांव की एक पॉश सोसायटी से गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्य रूप से हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाकर उनसे जबरन रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात है। एजीटीएफ की यह कार्रवाई राज्य में संगठित अपराध और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे तीन दर्जन से अधिक संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। सात आपराधिक मुकदमों में फरार चलने के कारण एसपी कोटपुतली द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

- **पुलिस के अनुसार, हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्यतः हाईवे पर स्थित होटल संचालकों से जबरन रंगदारी वसूलने में लिप्त है।**

एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में, एक विशेष टीम को इस हार्डकोर बदमाश को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राम सिंह द्वारा किया गया। टीम ने मुखबिरों को एक्टिव किया। इसके बाद हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार को उसके गुरुग्राम में होने की पुख्ता जानकारी मिली।

यह एक चुनौतीपूर्ण मिशन था, जहाँ टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेकी की। आरोपी गुड़गांव के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र की एक विशाल और लग्ज़री सोसायटी एम आर पाम हिल के एक फ्लैट में छिपा हुआ था।

टीम ने सोसायटी के नाकों पर सदस्य तैनात किए और गार्ड बनकर हेड कांस्टेबल सुधीर ने अंदर पल-पल की जानकारी हासिल की। सटीक स्थिति का पता चलते ही टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और गैंग्स्टर प्रदीप रावत को घेर कर दबोच लिया। टीम आरोपी को कोटपूतली लेकर आई है और उसे थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अन्य मामलों के खुलासे की पूरी संभावना है।

'अगर इमरान ज़िंदा हैं तो मिलने क्यों नही दिया जा रहा'

इमरान की पार्टी के लोगों ने इमरान की हत्या की आशंका जताई

रावलपिंडी, 27 नवंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवित होने को लेकर सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा गया है। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में उनके परिवार और परिजनों को कोई खबर नहीं दी गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और जापानी मीडिया में इमरान खान की जेल में मौत होने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने साढ़े पांच बजे नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुला ली है। इससे बड़ी अनहोनी की आशंका जन्म ले रही है। इन्हीं आशंकाओं के बीच खैबरपख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी बृहस्पतिवार को जब इमरान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया।

मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से जेल में मिलने से मना कर दिया गया। इसलिए वे जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले कई दिनों से इमरान खान की मौत हो जाने की अफवाहें पाकिस्तान से लेकर विदेशी मीडिया तक में हाहाकार मचा रही हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की खैबरपख्तूनख्वा में सरकार है। सोहेल अफरीदी इमरान खान की पार्टी के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। मगर उन्हें भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने मिलने से रोक दिया है। इमरान खान का परिवार और पीटीआई के कार्यकर्ता, शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ असिम मुनीर पर इमरान खान की जेल में ही हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हजारों इमरान समर्थक अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे यह प्रदर्शन अन्य शहरों में भी फैलता जा रहा है।

- **असल में अफगानिस्तान मीडिया ने बुधवार को दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी की अडियाला जेल में हत्या कर दी गई है, उसके बाद से ही भारी अफरातफरी का माहौल है।**

दरअसल अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी की आदियाला जेल में हत्या कर दी गई है। इससे पाकिस्तान में अफरातफरी के हालात बन गये हैं। इमरान खान के समर्थकों की मांग है कि अगर इमरान खान सुरक्षित और जीवित हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की मौत की रिपोर्ट को बकवास बताया है, लेकिन मुश्किल समय में इमरान खान को छोड़कर भागने की वजह से समर्थकों को उनकी बातों पर यकीन नहीं है।

स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन पर भाजपा समर्थकों द्वारा एक असामान्य गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, जो आमतौर पर राज्यस्तरीय मंत्रियों को राजधानी में नहीं मिलता।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर कई पूर्व-निर्धारित बैठकें हुईं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि पार्टी बिहार के बदलते राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी गंभीर है। गृह मंत्रालय पर तो भाजपा का नियंत्रण है ही, और अब वह स्पीकर पद पर काबिज होने की तैयारी में है, जिससे पार्टी के पास अब कानून-व्यवस्था और विधायी प्रक्रिया, दोनों का नियंत्रण होगा। यह दोहरा कब्जा भाजपा को बिहार में सत्ता का केन्द्र बना देता है, जिसके चलते नीतीश कुमार के पास काम करने की सीमित गुंजाइश ही बचती है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये घटनाक्रम भाजपा प्रेरित शासन के एक नए युग का संकेत हैं, जहां नीतीश मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब भाजपा के हाथों में है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में स्पेशल इन्टैंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया है। पीठ ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकेंगे, और मामले की शीघ्र सुनवाई का निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईआर लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर मौलिक चिंताएं उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर सामान्य मतदाताओं पर असंवैधानिक दबाव डालता है, जिनमें से कई निरक्षर हैं।

उन्होंने कहा, ''फॉर्म भरना मतदाता की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोग निरक्षर हैं और उन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता। अगर वे फार्म नहीं भर सकते, तो उन्हें (मतदाता सूची से) हटा दिया जाएगा, उन्होंने अदालत से संविधानिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने की अपील की।''

उन्होंने कहा कि एक बार किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाने के बाद, उसकी वैधता की मान्यता स्वत: ही बन जाती है, जब तक राज्य इसका विरोध नहीं करता। ''किसी भी बहिष्करण की प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए।''

सिब्बल ने यह भी कहा कि जब आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, यह धारक के पक्ष में एक अनुमान है। उन्होंने कहा, ''तो मेरे पक्ष में भी एक अनुमान है। मेरे पास आधार है। वह मेरा निवास है। आप इसे हटाना चाहते हैं... तो इसे एक प्रक्रिया से हटाइए और इसे इस कोर्ट में साबित होने दीजिए।'' हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने मृत मतदाताओं को सूची से हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह बताया कि सूची पंचायतों और सरकारी वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। उन्होंने कहा, ''हम शून्य में निर्णय नहीं करते। सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी।

हम प्रदूषण पर तुरंत समाधान की उम्मीद नहीं करें- सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (एमसी मेहता मामला) से संबंधित मामले को अगले सोमवार को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है लेकिनद्ध न्यायालय ने आगाह किया कि न्यायपालिका से इस स्तर के संकट का तुरंत समाधान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरूवार को इस मामले की तत्काल सूचीबद्धता के उल्लेख की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक ''स्वास्थ्य आपातकाल'' है। पीठ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को तदर्थ न्यायिक निर्देशों के बजाय, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जानकारी पर निर्भर रहना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की ''खतरनाक'' स्थिति को उजागर करने वाली न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''हम समस्या जानते हैं। हमें सभी कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है। कोई एक अकेला कारण नहीं है, ऐसा सोचना गलती होगी।''

- **सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तदर्थ न्यायिक निर्देशों की बजाय वैज्ञानिक व विशेषज्ञ जानकारी पर निर्भर रहना चाहिये।**

न्यायपालिका की सीमाओं का उल्लेख करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ''कोई अदालत क्या जादुई छड़ी चला सकती है? मुझे बताएं, हम क्या निर्देश दें, ताकि तुरंत स्वच्छ हवा मिल जाए?'' पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह समझना आवश्यक है कि सरकार ने कौन सी समितियां बनाई हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या कर रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों में कौन से समाधान व्यावहारिक हैं।

उपभोक्ता आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। ऐसे में इसमें केसर मिलाने का दावा भ्रामक है। परिवाद में बताया गया कि विज्ञापन में दाने-दाने में केसर का दम दिखाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। इससे एक ओर निर्माता कंपनी करोड़ों रुपए का व्यापार कर रही है और दूसरी ओर आमजन हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए घातक गुटखे का सेवन कर कैंसर जैसी बीमारी को न्यौता दे रहे हैं। परिवाद में गुहार की गई है कि विमल गुटखा के उत्पादन और विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाई जाए।

मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग ने तीनों अभिनेताओं और अभिनेत्री सहित निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

दिल्ली विस्फोट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकि उनका इस्तेमाल हमलों में किया जा सके।

एजेंसी के मुताबिक, वानी के खिलाफ सबूतों से पता चलता है कि उसने 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट में मदद के लिए आतंकवादी नेटवर्क को टेक्निकल सपोर्ट देना जारी रखा। ये गतिविधियां बड़े हमलों की साजिश का हिस्सा थीं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। एनआईए टीम वानी से दूसरे संभावित साथियों, ड्रोन सप्लाई नेटवर्क और टेक्निकल मॉड्यूल के बारे में पूछताछ करेगी।

मुंबई में सीट बंटवारे पर ठाकरे बंधुओं में मतभेद हुआ

मुंबई, 27 नवंबर। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच 75 सीटों को लेकर एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गतिरोध दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मध्य मुंबई स्थित उनके आवास शिवतीर्थ पर पूर्वाह्न में मुलाकात की।

एसआईआर भरते हुए बंगलादेशी गिरफ्तार

कोलकाता, 27 नवंबर। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बॉग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत गणना पत्र भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था। वह तब पकड़ा गया, जब उसने स्थानीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से नौ साल पहले मर चुके मोहसिन खान का गणना पत्र हासिल किया और उसे भरने की कोशिश कर रहा था। माथुर डांगी गाँव के वार्ड नंबर 20 के मोहसिन खान के परिवार के सदस्यों ने विवरण देखने के बाद इस धोखाधड़ी को भांप लिया और उसे पकड़कर डानकुनी पुलिस के हवाले कर दिया।

- **बंगलादेशी नदीम 15 साल पहले भारत आया था और आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था।**

इण्डो-अमेरिकन व्यापारिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन परिस्थितियों में समझौता होगा या नहीं, और यदि होगा तो किस रूप में, यह काफी हद तक दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा और समझौते की तैयारी पर निर्भर करेगा। सवाल यह है कि क्या कोई पक्ष नरमी दिखाने के लिए तैयार है?

कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि थोड़ी गुंजाइश मौजूद है। भारत कृषि व डेयरी क्षेत्र को व्यापक रूप से खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सेब, बादाम, अखरोट, कुछ प्रोसैस्ड फूड और गैर-जीएम अमेरिकी उत्पादों को सीमित मात्रा में अनुमति देने के लिए तैयार दिख रहा है। यह संकेत है कि भारत पूरी तरह बाजार खोले बिना, सीमित और नियंत्रित पहुंच देने पर विचार कर सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों (स्टील, ऑटो कॉम्पोनैंट्स) पर पहले ही भारी शुल्क लगा रखा है, जिससे यह दबाव बढ़ सकता है, खासकर उन सैक्टर्स की तरफ से, जो भारतीय सप्लाई चेन पर निर्भर हैं, कि व्यापक समझौते के बजाय सीमित छोटा समझौता स्वीकार कर लिया जाए।

फिर भी नज़दीकी समय में किसी बड़े नरम रुख की संभावना कम ही दिखती है। भारत के लिए कृषि और डेयरी सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा का आधार हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में सुरक्षा कम करने पर तीखी घरेलू प्रतिक्रिया हो सकती है। वहीं अमेरिका की कृषि लॉबी और खेती के सामान के निर्यातक भी भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर पहुंच की मांग छोड़ने वाले नहीं हैं।

ऐसे में सबसे अधिक संभावना यही है कि एक सीमित या ''मिनी-डील'' बन सकती है, जिसमें औद्योगिक व गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क संबंधी रियायतें शामिल होंगी, और कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों को नियंत्रित एवं सीमित शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। यह राजनीतिक और व्यापारिक रूप से दोनों देशों के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

संक्षेप में, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावटें खेती, डेयरी और रैगुलेटरी ऑटोनोमी में हैं। दोनों पक्षों के लिए समझौता नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह आर्थिक फायदों और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन बनाने पर निर्भर करेगा।

- **दूसरी ओर अमेरिका भी भारतीय मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने की मांग पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं।**
- **भारत अगर कुछ नर्म पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा सेब, बादाम आदि कुछ ''कृषि उत्पादों'' को बेचने की सीमित छूट दे सकता है।**
- **लगभग यह ही स्थिति भारत के औद्योगिक उत्पाद, जैसे स्टील, ऑटोपार्ट्स, टैक्सटाइल्स के बारे में है।**
- **अतः तुरंत, आनन-फानन में ''ट्रेड डील'' हो जाए, मुमकिन नहीं लगता। कुछ छोटी-मोटी मिनी ''ट्रेड डील'' जरूर हो सकती है।**

क्या बुलेट ट्रेन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईसीटीएस-2 सिग्नलिंग को लागू करने का इरादा भी किया है, लेकिन इस पर विचार-विमर्श जारी है। जून में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (एनएचआरसीएल) - जो एमएएचएसआर की कार्यान्वयन एजेंसी है - ने सिग्नलिंग और टेलीम्यूनिकेशंस कार्यों के लिए डीआरए-इन्फ्राकॉम सीमन्स संयुक्त उपक्रम को 4140 करोड़ रुपये का अनुबंध सौंपा। सीमन्स ने भारतीय रेलवे के प्रबंधकों को यह आश्वासन दिया है कि ''ड्यूल-यूज़'' सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे, ताकि अगर भारत के सार्वजनिक परिवहन ने बाद में लीकी केबल सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया तो वह इसके लिए तैयार हो गया।

दिल्ली- मेरठ रैपिड रेल और दिल्ली मेट्रो के लिए अपनाई गई रणनीतियों के अनुरूप, भारतीय रेलवे 320 किमी/घंटा की गति वाली ट्रेनसेट्स के लिए ''वेंडर न्यूट्रल'' सिग्नलिंग सिस्टम प्राप्त करने की योजना बना रहा है, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी की भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, इन बिड्स को बाद में जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि, भारतीय रेलवे की पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी या उपकरण खरीदने की मंशा जापान के साथ विवाद पैदा कर सकती है, जो परियोजना के वित्तपोषक हैं। दिसंबर 2015 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत, एक सेट वस्त्रों को जापान से खरीदना अनिवार्य होगा। शेष सामग्री के लिए जापान की स्वीकृति आवश्यक होगी। एमएएचएसआर पर कार्य कर रहे ठेकेदार पहले ही जापान की हठधर्मी के कारण पश्चिमी देशों से आयात किए गए सामान को मंजूरी देने में समस्या का सामना कर रहे हैं। एक कंपनी ने इस साल जर्मनी से आयातित कुछ घटकों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लगभग 50 करोड़ रुपये का नुकसान बताया है। इस कंपनी ने अब यूरोपीय निर्माताओं से और अधिक आयात करने की योजना रोक दी है।

असम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है, यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है, जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उससे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उनकी शादी कानूनी रूप से रद्द नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह कदम सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच गहरे मतभेदों को दर्शायेगा, जिनके बीच कांग्रेस की 2023 की बड़ी जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव है।

संभावित विकल्प के रूप में गृह मंत्री जी. परमेश्वर का नाम सामने आया है। वे सिद्धारमैया समर्थक और प्रभावशाली दलित नेता हैं। उन्होंने हाल में कहा, ''मैं हमेशा से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहा हूं,'' जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई।

यह रणनीति बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली की अगुवाई में हुई बैठक में तय की गई। जारकीहोली सिद्धारमैया के करीबी हैं। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि पार्टी के दिल्ली नेतृत्व को यह सवाल अब निपटाना ही होगा। जारकीहोली की शिवकुमार से भी मुलाकात हुई, लेकिन बैठक का विवरण सामने नहीं आया।

खड़गे और गांधी परिवार गुरुवार या शुक्रवार को इस मसले पर अंतिम चर्चा कर सकते हैं। खड़गे ने पत्रकारों से कहा, ''सोनिया, राहुल और मैं इस समस्या का समाधान कर देंगे।''

योजना यह है कि खड़गे-गांधी बैठक के बाद, सिद्धारमैया और शिवकुमार, दोनों को दिल्ली बुलाया जाएगा।

उधर डीके शिवकुमार ने अब तक टकराव की स्थिति नहीं बनाई है और राजनीतिक रूप से संतुलित बयान दिए हैं। उन्होंने तो अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पद, जिसे वे चाहते हैं, पर बने रहने का समर्थन भी सार्वजनिक रूप से किया है और अपने समर्थन में आए बयानों - जैसे रामनगर के विधायक इकबाल हुसैन का ''200 प्रतिशत पक्का'' वाला बयान, को भी हल्का किया है।

लेकिन उन्होंने कई बार संकेतों में तीखी बातें भी कही हैं, जिनमें वादों को निभाने की याद दिलाना शामिल है। माना जाता है कि उनका इशारा सीधे सिद्धारमैया की तरफ था।

सिद्धारमैया-शिवकुमार विवाद कांग्रेस की 2023 जीत के बाद शुरू हुआ। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया को चुना, जबकि शिवकुमार का मानना था कि जीत दिलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, इसलिए यह पद उन्हें मिलना चाहिए था।

इसके बजाय उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया, पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहने दिया गया। कांग्रेस का ''एक व्यक्ति, एक पद'' नियम इस मामले में ढीला किया गया। उसी समय एक 'समझौता' चर्चा में था, जिसका जिक्र शिवकुमार ने ''हम पांच-छह लोगों के बीच हुआ गुप्त समझौता'' कहकर किया था, जिसके अनुसार, आधे कार्यकाल के बाद सिद्धारमैया पद छोड़ देंगे।

पांच साल के कार्यकाल का मध्य बिंदु पिछले सप्ताह पार हो गया। तब से शिवकुमार खेमे के विधायक परिवर्तन की मांग जोर-शोर से उठा रहे हैं। शिवकुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे पद चाहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने का संकेत भी दिया था, जो मुख्यमंत्री पद पाने की इच्छा का प्रतीक है।

ईडी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण विवरण लीक करने के एवज में रिश्वत दी गयी थी। आरोप है कि इस जानकारी के लीक होने से मेडिकल कॉलेजों को जरूरी मापदंडों में हेरफेर करने और अवैध रूप से अनुमोदन लेने में मदद मिली। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, उनमें सात मेडिकल कॉलेज और निजी आरोपियों के ठिकाने शामिल हैं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908